रिजर्व बैंक ने क्लाउड आधारित वीडियो अनुप्रयोगों का उपयोग करते हुए वर्चुअल मोड से आयोजित विभिन्न अभिनव आंतरिक और बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से महामारी के दौरान भी मानव संसाधन कौशल को बढ़ाने का प्रयास जारी रखा। रिजर्व बैंक में जोखिम निगरानी और आंतरिक लेखा परीक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए वर्ष के दौरान कई उपाय शुरू किए गए। कोविड-19 महामारी के प्रतिसाद में, महत्वपूर्ण कारोबार प्रक्रियाओं को सुरक्षित किया ताकि अपने मानव संसाधनों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करते हुए रिजर्व बैंक की समय-संवेदनशील महत्वपूर्ण गतिविधियों की कारोबार निरंतरता और सुचारु संचालन को सुनिश्चित किया जा सके।

XI.1 इस अध्याय में रिजर्व बैंक के तीन महत्वपूर्ण पहलुओं- गवर्नेस, मानव संसाधन प्रबंधन और जोखिम निगरानी के अलावा आंतरिक लेखा परीक्षा, कॉर्पोरेट कार्यनीति और बजट, राजभाषा और परिसर से संबंधित विभागों की गतिविधियों पर चर्चा की गई है। अध्याय प्रमुख घटनाओं की समीक्षा करता है, वर्ष के प्रारंभ में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में 2020-21 के दौरान उनकी प्राप्ति का मूल्यांकन करता है और 2021-22 के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित करता है।

XI.2 वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मानव संसाधन को नयी भर्तियों, आंतरिक तथा बाह्य प्रशिक्षण के माध्यम से सशक्त किया गया। महामारी के प्रतिसाद में, ऑनलाइन और ई-लर्निंग मोड पर बड़े पैमाने पर भरोसा किया गया। आरबीआई अकादमी ने वर्ष के दौरान कई वेबिनार आयोजित किए, जिनमें से कुछ बाहरी एजेंसियों जैसे, आईएमएफ साउथ एशिया रिजनल ट्रेनिंग एण्ड टेक्निकल सपोर्ट सेंटर (आईएमएफ एसएआरटीटीएसी) और विश्व बैंक, के सहयोग से विनियमन और पर्यवेक्षण पर कोविड-19 के प्रभाव से लेकर बीग डेटा और फिनटेक जैसे उभरते क्षेत्रों से संबंधित विषयों पर थे। इसके अलावा, रिजर्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए अत्यधिक कारोबारी अनिश्चितता का प्रबंधन और लीडरशिप फाउंडेशन तथा महत्वपूर्ण संवाद पर कार्यशालाओं का भी आयोजन किया गया।

XI.3 वर्ष 2012 में अपनाए गए उद्यम व्यापी जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) फ्रेमवर्क के तहत केंद्रीय बोर्ड (सीसीबी) की समिति

के रिस्क टॉलरेंस स्टेटमेंट के अनुसार रिस्क टॉलरेंस लिमिट (आरटीएल) और रिस्क रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए वर्ष के दौरान एक संरचित प्रक्रिया लागू की गई है। प्रायोगिक आधार पर मुद्रा प्रबंध और भुगतान और निपटान प्रणाली का कार्य करने वाले विभागों के लिए आरटीएल तैयार किए गए। रिस्क टॉलरेंस फ्रेमवर्क के चरणबद्ध कार्यान्वयन की दिशा में, कुछ बाजार विभागों के लिए आंतरिक रूप से रिस्क टॉलरेंस फ्रेमवर्क रुख के अनुरूप वर्तमान में मौजूदा रिस्क टॉलरेंस लिमिट की समीक्षा प्रक्रिया चल रही है।

XI.4 वर्ष के दौरान निरीक्षण विभाग द्वारा जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए) के तहत मूल्यांकित जोखिम रेटिंग तथा परिचालन जोखिम के लिए जोखिम मूल्यांकन पद्धति (रैम-ओआर) के अनुसार निर्धारित जोखिम रेटिंग का लक्षित अभिसरण पूरा किया गया। रिजर्व बैंक में समयबद्ध और लागत प्रभावी तरीके से परियोजना कार्यान्वयन के प्रबंधन के लिए प्रभावी आंतरिक नियंत्रण को बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष के दौरान एक आईटी परियोजना की प्रायोगिक परियोजना लेखा परीक्षा सफलतापूर्वक की गई। कोविड-19 के प्रकोप से सभी क्षेत्रीय कार्यालयों/ कारोबार इकाइयों के लिए कॉर्पोरेट कार्यनीति और बजट विभाग (सीएसबीडी) द्वारा तैयार की गई कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) लागू करना आवश्यक हो गया। रिजर्व बैंक द्वारा की गई समयपूर्व आपदा प्रबंधन पहलों ने विशेष रूप से देश की भुगतान प्रणालियों और सामान्य रूप से बैंकिंग

प्रणाली के लिए निर्बाध रूप से 24X7 सेवाओं को सुनिश्चित किया।

XI.5 इसके अतिरिक्त, राजभाषा विभाग ने कुछ विभागों के लिए विभाग-विशिष्ट शब्दावली तैयार की और हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए बैंकिंग शब्दावली को अद्यतन करने के प्रयोजन से बैंकरों और प्रख्यात विद्वानों को शामिल करते हुए एक अंतर-संस्था समिति का गठन किया। परिसर विभाग ने रिज़र्व बैंक के भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण, रखरखाव और उन्नयन के अपने प्रयास जारी रखे। “हरित पहल” के अंतर्गत रिज़र्व बैंक के विभिन्न कार्यालयों और आवासीय इमारतों में सौर ऊर्जा जनरेशन संयंत्रों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन, वर्षा जल संरक्षण प्रणाली, सीवेज उपचार और अपशिष्ट जल उपचार प्रणालियां स्थापित की गईं।

XI.6 इस अध्याय को नौ खंडों में विभाजित किया गया है। खंड 2 में रिज़र्व बैंक के गवर्नेंस ढांचे से संबंधित गतिविधियों के बारे में बताया गया है। खंड 3 में मानव संसाधन विकास विभाग (एचआरएमडी) द्वारा मानव संसाधनों के क्षेत्र में वर्ष के दौरान किए गए प्रयासों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। उद्यम व्यापी जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क से संबंधित विकास खंड 4 में प्रस्तुत किया गया है। वर्ष के दौरान निरीक्षण विभाग के कार्य-कलापों की चर्चा खंड 5 में की गई है। सीएसबीडी जो रिज़र्व बैंक के लिए कार्यनीतियां और वार्षिक कार्ययोजनाएं बनाता और समन्वय करता है, का विवरण खंड 6 में दिया गया है। राजभाषा विभाग और परिसर विभाग की गतिविधियों और उपलब्धियों को क्रमशः खंड 7 और 8 में दिया गया है। अंत में अध्याय का निष्कर्ष दिया गया है।

2. गवर्नेंस संरचना

XI.7 भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) अधिनियम, 1934 के अनुसार केंद्रीय निदेशक मंडल को रिज़र्व बैंक के गवर्नेंस कार्य का दायित्व दिया गया है। इसमें अध्यक्ष के रूप में गवर्नर, उप गवर्नर, केंद्र सरकार द्वारा नामित निदेशक शामिल हैं। चार स्थानीय बोर्ड हैं, देश के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों के लिए प्रत्येकी एक, जो केंद्रीय मंडल को उनको संदर्भित मामलों के बारे में सलाह देते हैं तथा केंद्रीय मंडल द्वारा दिए गए कार्य करते हैं। केंद्र सरकार आरबीआई अधिनियम, 1934 के अनुसार स्थानीय बोर्डों में सदस्यों को भी नियुक्त करती है।

XI.8 केंद्रीय बोर्ड की सहायता के लिए तीन समितियां होती हैं: केंद्रीय बोर्ड समिति (सीसीबी), वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस) तथा भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए बोर्ड (बीपीएसएस)। इन समितियों के अध्यक्ष गवर्नर होते हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय बोर्ड में पांच उप समितियां भी होती हैं: लेखापरीक्षा और जोखिम प्रबंधन उप-समिति (एआरएमएस), मानव संसाधन प्रबंधन समिति (एचआरएम-एससी), भवन उप-समिति (बीएससी) सूचना प्रौद्योगिकी उप-समिति (आईटी-एससी) और कार्यनीति उप-समिति (एस-एससी)। इन उप समितियों की अध्यक्षता सामान्यतः बाह्य निदेशक ही करते हैं।

केंद्रीय बोर्ड और सीसीबी की बैठकें

XI.9 जुलाई 2020 से मार्च 2021 संक्रांति वर्ष¹ के दौरान केंद्रीय बोर्ड की पांच बैठकें आयोजित की गईं।

¹ 2020-21 से रिज़र्व बैंक के लेखा वर्ष में अप्रैल-मार्च यह परिवर्तन होने के कारण, रिज़र्व बैंक का पहला संक्रांति वर्ष केवल नौ महीने का था (जुलाई 2020-मार्च 2021)।

XI.10 जुलाई 2020 से मार्च 2021 के दौरान सीसीबी की 35 बैठकें हुईं, जिनमें से 26 इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से और नौ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गईं। सीसीबी ने रिज़र्व बैंक के साप्ताहिक मामलों की विवरणियों को अनुमोदित करने के साथ-साथ इसके वर्तमान कारोबार पर भी ध्यान दिया।

XI.11 पश्चिमी, पूर्वी क्षेत्र के स्थानीय बोर्डों की जुलाई 2020 से मार्च 2021 के दौरान दो बैठकें आयोजित कीं। उत्तरी क्षेत्र के स्थानीय बोर्ड की जुलाई 2020 से मार्च 2021 के दौरान तीन बैठकें आयोजित कीं। दक्षिणी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड (कोरम के अभाव में) के स्थान पर कार्य कर रही केंद्रीय बोर्ड की स्थायी समिति ने जुलाई 2020 से मार्च 2021 के दौरान दो बैठकें आयोजित कीं। केंद्रीय बोर्ड, इसकी समितियों और उप समितियों, स्थानीय बोर्डों और दक्षिणी क्षेत्र के लिए केंद्रीय बोर्ड की समिति की बैठकों में निदेशकों/सदस्यों की प्रतिभागिता का विवरण अनुबंध सारणी XI.1-5 में दिया गया है।

केंद्रीय बोर्ड/स्थानीय बोर्ड

XI.12 केंद्र सरकार ने श्री एम. राजेश्वर राव को उनके पद ग्रहण करने की तिथि से तीन साल के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में नियुक्त किया। श्री राव ने 9 अक्टूबर 2020 को पदभार ग्रहण किया।

XI.13 भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में श्री बी. पी. कानूनगो का कार्यकाल 2 अप्रैल 2021 को समाप्त हो गया।

XI.14 केंद्र सरकार ने श्री टी. रबी शंकर को उनके पद ग्रहण करने की तिथि से तीन साल के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में नियुक्त किया। श्री टी. रबी शंकर ने 3 मई 2021 को पदभार ग्रहण किया।

XI.15 केंद्रीय बोर्ड के तीन निदेशकों डॉ.अशोक गुलाटी, श्री मनीष सभरवाल और डॉ. प्रसन्न कुमार मोहंती का कार्यकाल 8 फरवरी 2021 को समाप्त हो गया। केंद्रीय बोर्ड के निदेशक श्री दिलीप एस. शंघवी का कार्यकाल 10 मार्च 2021 को समाप्त हो गया।

XI.16 केंद्र सरकार ने श्री तरुण बजाज के स्थान पर श्री अजय सेठ, सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को 24 अप्रैल 2021 से अगले आदेश तक भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नियुक्त किया।

कार्यपालक निदेशक

XI.17 कार्यपालक निदेशकों में डॉ. रबी एन.मिश्रा तथा श्रीमती नंदा एस. दवे 31 अगस्त 2020; श्रीमती लिली वडेरा 29 अक्टूबर 2020 तथा श्रीमती इंद्राणी बैनर्जी 27 नवंबर 2020 को सेवानिवृत्त हो गए। श्री एम. राजेश्वर राव ने उप गवर्नर का पद ग्रहण करने के लिए 8 अक्टूबर 2020 को रिज़र्व बैंक की सेवा से स्वेछानिवृत्ति ले ली। डॉ. मृदुल के. सागर को 1 जुलाई 2020 से, श्री सौरव सिन्हा और विवेक दीप को 1 सितंबर 2020 से, श्री जयंत कुमार दाश को 12 अक्टूबर 2020 से, श्री आर. सुब्रमनियन, श्री रोहित जैन तथा श्री राधा श्याम रथ को 11 दिसंबर 2020 से, कार्यपालक निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया। श्री टी. रबी शंकर ने उप गवर्नर का पद ग्रहण करने के लिए 3 मई 2021 को रिज़र्व बैंक की सेवा से स्वेछानिवृत्ति ले ली। श्री जोस जे.कडूर को 3 मई 2021 से कार्यपालक निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया।

3. मानव संसाधन विकास के प्रयास

XI.18 रिज़र्व बैंक के पास परिचालन का एक विस्तृत कैनवास है, जिसे अपने दायित्व को पूरा करने के लिए आंतरिक क्षमताओं के एक मजबूत व्यवस्था की आवश्यकता होती है। मानव संसाधन प्रबंध विभाग (एचआरएमडी) स्टाफ की कार्यक्षमता बढ़ाने और कार्य के लिए अपेक्षित उनकी प्रभावकारिता हेतु कर्मचारियों की संभावित कार्यक्षमताओं का पता लगाकर टीमवर्क का एक वातावरण बनाने में एनेबलर और समन्वयक की भूमिका निभाता है। वर्ष के दौरान, विभाग ने प्रशिक्षण और संगठनात्मक विकास, कार्यनिष्पादन प्रबंधन, संगठनात्मक संरचना और परिचालन तथा कर्मचारियों की नियुक्ति जैसे चार स्तंभों पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा और महामारी के बीच कारोबार निरंतरता बनाए

रखने की चुनौती को उठाने के अलावा प्रशिक्षण, भर्ती (भर्ती संबंधी चुनिंदा प्रक्रियाओं की समीक्षा सहित) और कर्मचारी कल्याण से संबंधित विभिन्न गतिविधियों को अंजाम दिया। वर्ष के दौरान इन और अन्य क्षेत्रों में की गई प्रमुख गतिविधियों के साथ-साथ 2020-21 के लिए निर्धारित लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति और वर्ष 2021-22 की कार्ययोजना को भी नीचे रेखांकित किया गया है।

वर्ष 2020-21 की कार्ययोजना: कार्यान्वयन की स्थिति

2020-21 के लिए निर्धारित लक्ष्य

XI.19 पिछले वर्ष में विभाग ने उत्कर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- कार्यनिष्पादन मूल्यांकन प्रणाली और वर्तमान प्रशिक्षण नीति की समीक्षा करना (पैरा XI.20)
- विशेष पर्यवेक्षी और विनियामक संवर्ग स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया जारी रखना (पैरा XI.21); और
- अधिकारियों की चुनिंदा श्रेणी के लिए एक कार्यक्षमता मैपिंग फ्रेमवर्क तैयार करना (पैरा XI.22)।

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

XI.20 कार्यनिष्पादन मूल्यांकन प्रणाली के चुनिंदा पहलुओं को मात्रात्मक पहलुओं के अलावा सॉफ्ट स्किल्स को कवर करने वाली अधिक समग्र प्रणाली बनाने की दृष्टि से संशोधित करने का प्रस्ताव किया गया था। सीधी भर्ती चैनल के माध्यम से लिए गए ग्रेड 'बी' अधिकारियों के इंडक्शन प्रशिक्षण को नया रूप दिया गया और एक अधिक केंद्रित कार्यक्रम लागू किया गया। स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति योजना को वृहद रूप से ध्यान दिए जाने तथा जवाबदेही तय करने के उद्देश्य से संशोधित किया गया।

XI.21 विनियामक और पर्यवेक्षी क्षेत्रों में विशेषज्ञता के निर्माण पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने के लिए पर्यवेक्षी/विनियामक विभागों से जुड़े अधिकारियों के लिए कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर (सीओएस) की स्थापना के लिए उचित सहायता की गयी।

XI.22 वर्ष के दौरान एक व्यापक कार्यक्षमता प्रबंधन फ्रेमवर्क की रूपरेखा तैयार की गयी (बॉक्स XI.1)।

प्रमुख गतिविधियां

आंतरिक प्रशिक्षण

XI.23 कौशल और ज्ञान विकास पहलें तकनीकी और व्यवहार कौशल को मजबूत करने पर केंद्रित हैं ताकि व्यक्तिगत विकास

बॉक्स XI.1

रिजर्व बैंक का कार्यक्षमता प्रबंधन फ्रेमवर्क

कार्यक्षमता प्रबंधन फ्रेमवर्क अपेक्षित ज्ञान, कौशल, योग्यता और व्यक्तित्व लक्षणों का वर्णन करता है जो एक सफल केंद्रीय बैंकर की उसकी संबंधित कार्यात्मक भूमिका में प्रोफाइल बनाते हैं। विभिन्न कार्यों में कार्यनिष्पादन को मापने के लिए यह ग्रहणशक्ति और सुसंगत दृष्टिकोण प्रदान करता है।

यह फ्रेमवर्क, अन्य प्रयोजनों के साथ-साथ, प्रमुख रूप से कार्य अनुकूल - योग्य व्यक्ति नियोजित करने के जरिए मानव संसाधनों को अनुकूल बनाने में

मदद करता है। फ्रेमवर्क में कार्यक्षमता और उनका विवरण, विभिन्न प्रवीणता स्तरों पर व्यवहारिक संकेतक, अधिकारियों की कार्यक्षमता के मैपिंग के लिए मूल्यांकन मॉडल और कार्यक्षमता की आवधिक समीक्षा तथा अद्यतनीकरण के लिए व्यवस्था शामिल हैं।

वर्ष 2021 में इस फ्रेमवर्क को रिजर्व बैंक में कार्यान्वयित करने का उद्देश्य है।

स्रोत: आरबीआई

सारणी XI.1 : रिजर्व बैंक के प्रशिक्षण संस्थानों में आयोजित कार्यक्रम

प्रशिक्षण संस्थान	2018-19 (जुलाई -जून)		2019-20 (जुलाई -जून)		2020-21 (जुलाई - मार्च)	
	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
आरबीआई अकादमी	22	546 (38)	21	476 (2)	25	840
आरबीएससी, चेन्नै	152	3,125 (499)	110	2,826 (85)	89	3,629 (72)
सीएबी, पुणे	179	5,542 (51)	126	3,891 (37)	183	10,308 (45)
जेडटीसी (श्रेणी-I)	116	2,271	92	1,667	135	3,682
जेडटीसी (श्रेणी-III)	76	1,877	94	2,648	104	4,568
जेडटीसी (श्रेणी-IV)	46	1,158	30	604	11	417

आरबीएससी : रिजर्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय   सीएबी : कृषि बैंकिंग महाविद्यालय
टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े विदेशी प्रतिभागियों और/या बाह्य संस्थाओं के प्रतिभागियों से संबंधित हैं।
स्रोत : आरबीआई

को सुगम बनाया जा सके और कार्य की प्रभावशीलता में सुधार किया जा सके। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक के प्रशिक्षण संस्थानों (प्रसं) और आंचलिक प्रशिक्षण केंद्रों (जेडटीसी) द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए गए (सारणी XI.1)। वर्ष के दौरान इनमें से कई प्रशिक्षण कार्यक्रम महामारी-प्रेरित वातावरण के कारण ऑनलाइन मोड के माध्यम से आयोजित किए गए।

आरबीआई अकादमी

XI.24 अकादमी ने उपयोगकर्ता विभागों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए उनके साथ मिलकर कार्य किया और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए विभागों की आवश्यकतानुसार अनुकूल बनाया। महामारी के कारण ऑनलाइन मोड में ध्यान केंद्रित करने के साथ, अकादमी ने वर्ष के दौरान विनियमन और पर्यवेक्षण पर कोविड-19 के प्रभाव (आईएमएफ एएसएआरटीटीएसी के सहयोग से), और बीग डेटा और फिनटेक (विश्व बैंक के सहयोग से) सहित कई वेबिनार आयोजित किए। इसके अलावा रिजर्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए, अत्यधिक कारोबारी अनिश्चितता का प्रबंधन और लीडरशिप फाउंडेशन तथा महत्वपूर्ण संवाद पर कार्यशालाओं का भी आयोजन किया। ऑनलाइन कार्यक्रमों को

और अधिक प्रभावी बनाने के लिए वर्ष के दौरान किए गए प्रमुख प्रयासों में लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस) का अधिक उपयोग, लाइव पोल/क्विज और सिमुलेशन अभ्यास शामिल हैं। इन मॉड्यूल से रिजर्व बैंक द्वारा पहचानी गई मुख्य कार्यक्षमताओं में कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने में सहायता मिलेगी।

बाह्य संस्थानों में प्रशिक्षण

XI.25 रिजर्व बैंक बाह्य संस्थानों में उपलब्ध विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए भारत और विदेश में स्थित संस्थानों में विशेष प्रशिक्षण, सेमिनार और सम्मेलनों में भाग लेने के लिए अपने अधिकारियों को प्रतिनियुक्त करता है (सारणी XI.2)। श्रेणी III और IV के कर्मचारियों को भी भारत में स्थित बाह्य संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है। हालाँकि, यह निर्णय लिया गया कि, महामारी के कारण, स्थिति सामान्य होने तक केवल ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ही प्रतिनियुक्ति की जाएगी।

अध्ययन योजना

XI.26 वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक के आठ अधिकारियों ने विदेशों में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने की योजना का तथा तीन अधिकारियों ने रिजर्व बैंक स्वर्ण जयंती योजना का लाभ उठाया।

सारणी XI.2 : भारत और विदेश स्थित बाह्य प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या

वर्ष	भारत में प्रशिक्षित (बाह्य संस्थान)	विदेश में प्रशिक्षित
1	2	3
2018 -19	952	378
2019 - 20	696	139
2020 - 21*	194	258

*: ऑनलाईन मोड

टिप्पणी: 2020-21 के आंकड़े जुलाई 2020- मार्च 2021 से संबंधित हैं, जबकि पिछले वर्षों के आंकड़े जुलाई-जून से संबंधित हैं।

स्रोत : आरबीआई।

अन्य नवोन्मेषी कार्य

अनुदान और वृत्तिदान

XI.27 बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में अनुसंधान, प्रशिक्षण और परामर्श को प्रोत्साहित करने के लिए रिज़र्व बैंक ने इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान (आईजीआईडीआर), मुंबई को ₹18.0 करोड़, उच्चस्तरीय वित्तीय अनुसंधान और अध्ययन केंद्र (कैफरल), मुंबई को ₹2.8 करोड़, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (एलएसई) इंडिया आब्जर्वेटरी और आईजी पटेल चेयर को ₹0.8 करोड़, भारतीय बैंक प्रबंधन संस्थान (आईआईबीएम), गुवाहाटी को ₹0.5 करोड़, राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान (एनआईबीएम), पुणे को ₹0.4 करोड़ का वित्तीय अनुदान प्रदान किया।

औद्योगिक संबंध

XI.28 वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहे। महामारी के कारण अधिकारियों और कर्मचारियों/कामगारों की मान्यता-प्राप्त एसोसिएशनों/फेडरेशनों के साथ सेवा स्थितियों और कर्मचारी कल्याण के उपायों के विविध मामलों के संबंध में वर्चुअल माध्यम से चर्चा की गई। जुलाई 2020 से मार्च 2021 के दौरान मानव संसाधन प्रबंध विभाग, केंद्रीय कार्यालय ने मान्यता-प्राप्त यूनियन एसोसिएशन के साथ कुल छह बैठकें

की। क्षेत्रीय कार्यालयों ने भी मान्यता-प्राप्त ट्रेड यूनियनों की स्थानीय इकाइयों के साथ अपना संचार निर्बाध रखा।

सेवानिवृत्ति लाभ

XI.29 भारत सरकार से सफल चर्चा के आधार पर, कुछ शर्तों के अधीन, अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) योजना में शामिल कर्मचारियों/सेवानिवृत्त कर्मचारियों/ दिवंगत कर्मचारियों के पात्र परिवार के सदस्यों को रिज़र्व बैंक की पेंशन योजना में स्विच ओवर करने के लिए एक अंतिम विकल्प की अनुमति देने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, 552 सेवारत कर्मचारियों, 1,453 सेवानिवृत्त कर्मचारियों और मृत कर्मचारियों के 162 परिवार के सदस्यों ने रिज़र्व बैंक की पेंशन योजना में शामिल होने का विकल्प चुना।

भर्तियां और स्टाफ संख्या

XI.30 वर्ष 2020 (जनवरी से दिसंबर) के दौरान रिज़र्व बैंक ने विभिन्न संवर्गों में कुल 61 कर्मचारियों की भर्ती की (सारणी XI.3)। महामारी के कारण रुकी हुई भर्ती प्रक्रिया 2020 की दूसरी छमाही में फिर से शुरू हो पाई। इस तरह, 2020 के दौरान शुरू की गई प्रक्रियाओं में भर्ती किए गए अधिकांश कर्मचारी जनवरी-मार्च 2021 के दौरान रिज़र्व बैंक में भर्ती हो गए। रिज़र्व बैंक ने वर्ष के दौरान ग्रेड बी (डीआर) में अधिकारियों की भर्ती से संबंधित अपनी प्रक्रियाओं के चुनिंदा पहलुओं की भी समीक्षा की। जनवरी से मार्च 2021 की अवधि के दौरान 442 कर्मचारियों

सारणी XI.3: रिज़र्व बैंक द्वारा 2020* में की गई भर्तियां

श्रेणी	जिसमें से:			
	कुल	अ.जा	अ.ज.जा	ओबीसी
1	2	3	4	5
श्रेणी I	9	2	-	1
श्रेणी III	7	4	-	1
श्रेणी IV	45	-	-	32
कुल	61	6	-	34

*जनवरी से दिसंबर - : शून्य

स्रोत : आरबीआई।

सारणी XI.4 : रिज़र्व बैंक* की स्टाफ संख्या

श्रेणी	कुल संख्या		श्रेणी-वार संख्या						कुल संख्या का प्रतिशत		
			अ.जा.		अ.ज.जा		ओबीसी		अ.जा.	अ.ज.जा	ओबीसी
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
श्रेणी I	6,670	6,121	1,051	976	435	413	1,147	1,159	15.95	6.75	18.93
श्रेणी III	3,264	3,051	487	468	199	191	892	866	15.34	6.26	28.38
श्रेणी IV	3,522	3,104	877	724	291	249	682	672	23.32	8.02	21.65
Total	13,456	12,276	2,415	2,168	925	853	2,721	2,697	17.66	6.95	21.97

*दिसंबर के अंत में
स्रोत : आरबीआई।

की भर्ती की गई जिसमें से श्रेणी I के 195 तथा श्रेणी III के 247 कर्मचारी हैं।

XI.31 रिज़र्व बैंक के पूर्ण कालिक कर्मचारियों की कुल संख्या 31 दिसंबर 2020 को 12,276 थी। इनमें से श्रेणी I में 6,412, श्रेणी III में 3,145 और श्रेणी IV में 3,254 कर्मचारी थे, एक वर्ष पहले की स्थिति में 8.8 प्रतिशत की कमी आयी (सारणी XI.4)। 31 मार्च 2021 को कर्मचारियों की कुल संख्या 12,406 थी।

XI.32 दिसंबर 2020 की समाप्ति पर रिज़र्व बैंक में भूतपूर्व सैनिकों की संख्या 940 थी जबकि दिव्यांग कर्मचारियों की कुल संख्या 302 थी (सारणी XI.5)। वर्ष 2020 के दौरान भूतपूर्व सैनिक और बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) की भर्ती नहीं की गई थी, जनवरी-मार्च 2021 के दौरान श्रेणी I में तीन पीडब्ल्यूबीडी की भर्ती की गयी।

XI.33 वर्ष 2020 (जनवरी से दिसंबर) के दौरान, प्रबंधन और अखिल भारतीय रिज़र्व बैंक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और बुद्धिस्ट फेडरेशन के बीच रिज़र्व बैंक में आरक्षण नीति लागू करने के संबंध में विचार-विमर्श के लिए एक बैठक आयोजित की गई। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक आयोजित की गई।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम

XI.34 वर्ष 1998 से कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए एक औपचारिक शिकायत निपटान प्रणाली कार्य कर रही है। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और समाधान) अधिनियम और नियम 2013 के अनुसार वर्ष 2014-15 में जारी नए विस्तृत दिशा-निर्देशों से इसे सशक्त किया गया है। जनवरी-दिसंबर 2020 के दौरान दो

सारणी XI.5 : भूतपूर्व सैनिकों और पीडब्ल्यूबीडी* की कुल संख्या

श्रेणी	भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम)	पीडब्ल्यूबीडी (बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति)			
		दृष्टिबाधित (वीआई)	बधिर (एचआई)	शारीरिक विकलांग (ओएच)	बौद्धिक दिव्यांगता**
1	2	3	4	5	6
श्रेणी I	230	34	-	108	-
श्रेणी III	171	35	7	60	4
श्रेणी IV	539	9	-	45	-

* दिसंबर 2020 के अंत में

:- शून्य

** दिव्यांग अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार बौद्धिक दिव्यांगता एक ऐसी स्थिति है जिसमें बौद्धिक कार्यशीलता (तार्किकता, अधिगम और समस्या समाधान) और अनुकूलनीय व्यवहार दोनों में विशिष्ट रूप में बाधित होते हैं जो 'विशेष अधिगम अक्षमता' और 'स्वलीनता (ऑटिज्म) स्प्रेक्ट्रम डिसऑर्डर' सहित प्रतिदिन के सामाजिक और व्यावहारिक कौशल शामिल हैं।

स्रोत : आरबीआई।

शिकायतों का निपटान किया गया जिसमें से एक शिकायत दिसंबर 2019 को समाप्त छमाही में प्राप्त हुई थी। जनवरी-मार्च 2021 के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। नए भर्ती कर्मचारियों, वेंडरों और संविदा पर कार्य करने वाले कर्मचारियों सहित सभी स्टाफ-सदस्यों को जागरूक बनाने के लिए कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों के साथ-साथ भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पैनल में शामिल गैर सरकारी संगठनों द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यशालाओं/प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए आंतरिक समिति के सदस्यों को भी नामित किया गया था।

सूचना का अधिकार (आरटीआई)

XI.35 सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत रिजर्व बैंक को 1 जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 के दौरान सूचना के लिए 15558 अनुरोध और 1225 अपीलें प्राप्त हुईं। वर्ष के दौरान आंचलिक प्रशिक्षण केंद्र, चेन्नै और कोलकाता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम पर दो प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

कोविड-19 महामारी का प्रतिसाद

XI.36 कर्मचारियों के कल्याण को सुनिश्चित करने और कारोबार निरंतरता बनाए रखने के लिए मार्च 2020 में महामारी की शुरुआत में की गई पहलों को बुनियादी वास्तविकताओं के आधार पर उपयुक्त संशोधनों के साथ आगे बढ़ाया गया। कोविड-19 जैसे महामारी से उत्पन्न किसी भी प्रकार की आपात स्थिति या संकट की स्थिति से प्रभावित लोगों की सहायता करने के लिए भारत सरकार के आह्वान पर बैंक के कर्मचारियों ने पीएम केयर फंड को कुल ₹ 7.30 करोड़ रुपये का योगदान दिया। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप लॉकडाउन की अवधि के दौरान ड्यूटी पर तैनात संविदा/आउटसोर्स कर्मियों को कार्यालय में उनकी उपस्थिति पर ध्यान दिए बिना ड्यूटी पर माना गया और तदनुसार भुगतान किया गया। संविदा मॉडल के तहत स्टाफ कैंटीन/अधिकारियों के लाउंज में कैटरिंग ठेकेदारों द्वारा नियमित

आधार पर सीधे नियोजित कामगारों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया गया। भारत सरकार द्वारा टीकाकरण प्रोटोकॉल जारी करने के बाद, कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को टीकाकरण करने के लिए अस्पतालों के साथ व्यवस्था की गई। रिजर्व बैंक के घर से काम करने वाले कर्मचारियों के अनुपात को सरकार के दिशानिर्देशों तथा मौजूदा परिस्थिति के अनुसार पर्याप्त रूप से विनियमित करते हुए स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

वर्ष 2020-21 के लिए कार्ययोजना

XI.37 वर्ष के लिए रोडमैप के अंतर्गत विभाग के लिए निम्नलिखित माइलस्टोन शामिल किए गए हैं:

- अंतरराष्ट्रीय/बहुपक्षीय बैठकों में रिजर्व बैंक के (भारत के) विचारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए डोमेन विशेषज्ञों का एक पूल विकसित करने के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय बैठकों/सम्मेलनों से संबंधित जानकारी में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए एक उपयुक्त उत्तराधिकार योजना तैयार करना (उत्कर्ष);
- सभी कार्यनीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए संगठनात्मक संरचना की समीक्षा करना और उसमें संशोधन करना (उत्कर्ष);
- अपने प्रशिक्षण और विकास से संबंधित प्रयासों पर सक्रिय ध्यान देने के लिए अपने प्रयासों को जारी रखना। रिजर्व बैंक में मिश्रित अध्ययन की अवधारणा के कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए प्रतिष्ठित विक्रेताओं से ई-लर्निंग सामग्री की खरीद तथा एक अध्ययन प्रबंधन प्रणाली शुरू करने की योजना तैयार करना।
- भर्ती नीतियों, विशेष रूप से अधिकारी स्तर, की दक्षता बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक सर्विसेज बोर्ड के परामर्श से उपयुक्त परिवर्तन करना।

4. उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन

XI.38 रिज़र्व बैंक द्वारा उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) को वर्ष 2012 में जोखिम एक्सपोजरों के प्रबंधन के लिए समेकित मूल्यांकन विकसित करने, जोखिम प्रबंधन के लिए 'साइलो आधारित' दृष्टिकोण से 'संपूर्ण कारोबार' दृष्टिकोण को अपनाया गया था। रिज़र्व बैंक में ईआरएम के निर्माण और परिचालन के लिए जोखिम निगरानी विभाग (आरएमडी) नोडल विभाग है।

वर्ष 2020-21 के लिए कार्ययोजना – कार्यान्वयन की स्थिति

वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित लक्ष्य

XI.39 पिछले वर्ष में विभाग द्वारा उत्कर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए थे:

- वर्तमान रिस्क टॉलरेंस फ्रेमवर्क की समीक्षा (उत्कर्ष); [पैरा XI.40];
- क्रेडिट जोखिम की प्रभावी निगरानी को सुगम बनाने के उद्देश्य से पोर्टफोलियो आधारित जोखिम पर क्रेडिट मूल्य /अपेक्षित कमी (वीएआर/ईएस) मॉडल को एक अतिरिक्त जोखिम निगरानी/रिपोर्टिंग टूल के रूप में विकसित करना (उत्कर्ष)। [पैरा XI.41];
- रिज़र्व बैंक की क्रेडिट जोखिम के सशक्त मूल्यांकन के लिए एक दबाव परीक्षण फ्रेमवर्क तैयार करना। (पैरा XI.42)

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

वर्तमान रिस्क टॉलरेंस फ्रेमवर्क की समीक्षा

XI.40 केंद्रीय बोर्ड की समिति (सीसीबी) का रिस्क टॉलरेंस स्टेटमेंट, रिस्क टॉलरेंस सीमा (आरटीएलएस) निर्धारित करने के लिए एक व्यापक मार्गदर्शन प्रदान करता है। आरटीएलएस तथा रिस्क रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए एक संरचित प्रक्रिया लागू की गई है। प्रायोगिक आधार पर मुद्रा प्रबंध और

भुगतान और निपटान प्रणाली का कार्य करने वाले विभागों के लिए आरटीएल तैयार किए गए हैं। रिस्क टॉलरेंस फ्रेमवर्क के चरणबद्ध कार्यान्वयन के भाग के रूप में आंतरिक रिस्क टॉलरेंस फ्रेमवर्क रुख के अनुरूप वर्तमान में कुछ बाजार विभागों के लिए रिस्क टॉलरेंस लिमिट समीक्षा की जा रही है।

पोर्टफोलियो आधारित जोखिम/अपेक्षित कमी पर क्रेडिट मूल्य (वीएआर/ईएस) मॉडल का विकास

XI.41 पोर्टफोलियो आधारित जोखिम पर क्रेडिट मूल्य /अपेक्षित कमी (वीएआर/ईएस) मॉडल को एक अतिरिक्त जोखिम निगरानी/रिपोर्टिंग टूल के रूप में विकसित करने की योजना है। इससे संबंधित आवश्यक कार्य पूरा हो गया है। हालाँकि, संबंधित कारोबारी विभागों के रिस्क टॉलरेंस फ्रेमवर्क की समीक्षा के बाद अंतिम मॉडलिंग और मानदंड निर्धारित किए जाएंगे।

दबाव परीक्षण फ्रेमवर्क का विकास

XI.42 दबाव परीक्षण फ्रेमवर्क का विकास यह निगरानी के लिए एक अतिरिक्त टूल है तथा संबंधित कारोबारी विभागों के रिस्क टॉलरेंस फ्रेमवर्क की समीक्षा के बाद इस पर कार्य किया जाएगा।

अन्य नवोन्मेषी कार्य

मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी

XI.43 मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीसो) निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार है; (ए) सूचना सुरक्षा जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क को परिभाषित करना; (बी) सूचना सुरक्षा नीति तैयार करना तथा उसके पालन की निगरानी करना; (सी) पहचान किए गए जोखिमों को दूर करने के लिए उपयुक्त सुरक्षा प्रौद्योगिकी समाधानों की सिफारिश करना; (डी) आवश्यकताओं के कार्यान्वयन के समर्थन में आवश्यक सलाह देना; (ई) खतरों को कम करने के लिए उनकी पहचान करना, प्रतिक्रिया और बहाली संचालन का प्रबंधन; और (एफ) संगठन में और संबंधित बाहरी एजेंसियों के

साथ सूचना सुरक्षा संबंधी मुद्दों का समन्वय।

XI.44 रिज़र्व बैंक में सूचना सुरक्षा के कार्य में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथा के रूप में स्वीकृत एंटरप्राइज रिस्क गवर्नेंस मॉडलों से अपनाए गए त्रि-स्तरीय सुरक्षा मॉडल का अनुसरण किया जाता है। व्यवसाय स्वामित्व वाले विभागों की परिचालन टीम और डीआईटी सुरक्षा की पहली पंक्ति अर्थात् कार्यान्वयन को तैयार करता है। सीसो सुरक्षा की दूसरी पंक्ति में सूचना सुरक्षा जोखिम के मूल्यांकन और निगरानी में एक सक्रिय प्रमुख भूमिका निभाता है। निरीक्षण विभाग सुरक्षा की तीसरी पंक्ति बनाता है अर्थात्, आश्वासना।

वर्ष 2021-22 के लिए कार्ययोजना

XI.45 वर्ष के लिए विभाग की कार्ययोजना में निम्नलिखित लक्ष्य प्रस्तावित है:

- अन्य परिचालन क्षेत्रों के लिए आरटीएल का रोल-आउट (उत्कर्ष);
- आईटी और साइबर जोखिम की मात्रा निर्धारण (उत्कर्ष); और
- परिचालन जोखिम के लिए जोखिम मूल्यांकन पद्धति की समीक्षा।

5. आंतरिक लेखापरीक्षा/निरीक्षण

XI.46 निरीक्षण विभाग रिज़र्व बैंक के आंतरिक नियंत्रण और गवर्नेंस प्रक्रिया की जांच, मूल्यांकन तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और जोखिम आधारित लेखापरीक्षा (आरबीआईए) के अंतर्गत उच्च प्रबंधन और केंद्रीय बोर्ड को जोखिम से निपटने का आश्वासन देता है। विभाग रिज़र्व बैंक में समवर्ती लेखापरीक्षा (सीए) सिस्टम एंड कंट्रोल सेल्फ असेसमेंट ऑडिट (सीएसएए) के कामकाज पर भी नजर रखता है। आरबीआईए, सीए और सीएसएए कार्य लेखापरीक्षा प्रबंधन और जोखिम निगरानी प्रणाली (एएमआरएमएस) नामक स्वचालित प्रणाली के माध्यम से किए जाते हैं। विभाग केंद्रीय बोर्ड की लेखापरीक्षा और जोखिम

प्रबंधन समिति (एआरएमएस) और आंतरिक लेखापरीक्षा की निगरानी करने वाली कार्यपालक निदेशकों की समिति (ईडीसी) के सचिवालय के रूप में भी कार्य करता है।

वर्ष 2020-21 के लिए कार्ययोजना: कार्यान्वयन स्थिति

वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित लक्ष्य

XI.47 पिछले वर्ष, विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- रिज़र्व बैंक की सभी उच्च मूल्य आईटी और गैर आईटी परियोजनाओं के लिए परियोजना लेखापरीक्षा का कार्यान्वयन करना (उत्कर्ष); [पैरा XI.48]
- आरबीआईए के संबंध में रेम-ओआर के अनुसार जोखिम रेटिंग का संवर्धित अभिसरण (उत्कर्ष); [पैरा XI.49]
- एआरएमएस और उच्च प्रबंधन को प्रभावी जोखिम आश्वासन के लिए एएमआरएमएस डेटा माइनिंग, विश्लेषण और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) रिपोर्टिंग डैशबोर्ड क्षमताओं को लीवरेज करना (उत्कर्ष); [पैरा XI.50]
- प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से ज्ञान और कार्यक्षमता का विकास करना (उत्कर्ष); [पैरा XI.51] और
- रिज़र्व बैंक में संशोधित जोखिम रेटिंग और स्कोरिंग प्रणाली का कार्यान्वयन करना। (पैरा XI.52)

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

XI.48 वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों के अनुसरण में, विभाग ने प्रोजैक्ट के प्लान के अनुसार रिज़र्व बैंक में समय पर और किफायती परियोजना कार्यान्वयन प्रबंधन के लिए एक प्रभावी आंतरिक नियंत्रण वातावरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आईटी प्रोजैक्ट की सफल प्रायोगिक परियोजना लेखा परीक्षा की। परियोजना लेखा परीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य परियोजना तैयार करना, स्वरूप और जिम्मेदारियों की सीमा, परियोजना प्रबंधन

टीम के अधिकार और जवाबदेही, संसाधनों का उपयोग, परियोजना को समय पर पूरा करना और सुपुर्दगी, परियोजना का मूल्यांकन करके परियोजना के निष्पादन के संबंध में एक स्वतंत्र, वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन प्रदान करना।

XI.49 विभाग ने वर्ष के दौरान रैम-ओर के अनुसार निर्धारित आरबीआईए और जोखिम रेटिंग के तहत मूल्यांकन किए गए जोखिम रेटिंग के लक्षित अभिसरण को भी प्राप्त किया है।

XI.50 एएमआरएमएस के आरबीआईए और सीए कार्य का स्वचालन पिछले वर्ष के दौरान पूर्ण हो गया था, विभाग ने सीएसए कार्य के स्वचालन पर ध्यान केंद्रित किया और वर्ष के दौरान इसे भी सफलतापूर्वक पूरा किया। एएमआरएमएस के माध्यम से स्वचालन में ऑडिट की योजना और संचालन; ऑडिट रिपोर्टिंग में एकरूपता और मानकीकरण; प्रस्तुती; अनुपालनों का प्रसंस्करण और निगरानी; डेटा एनालिटिक्स और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर (केपीआई) से संबंधित रिपोर्टिंग डैशबोर्ड्स, डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड मैनेजमेंट, तथा एकीकृत अलर्ट जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। इससे बढ़ी हुई आंतरिक लेखा परीक्षा प्रभावकारिता, परिचालन कार्यक्षमता, गोपनीयता, सहज रिपोर्टिंग, कागज रहित परिवेश (कम कार्बन फुट प्रिंट) और सीधे प्रसंस्करण (एसटीपी) से आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यों, जोखिम प्रबंधन और जोखिम आश्वासन कार्यों के बीच तालमेल बना है।

XI.51 विभाग ने रिज़र्व बैंक के सभी केंद्रीय कार्यालय विभागों, क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों को कवर करते हुए एएमआरएमएस में स्वचालन पर कई प्रशिक्षण/कार्यशालाओं के माध्यम से सभी उपयोगकर्ताओं के बीच जागरूकता लाकर ज्ञान और क्षमता निर्माण को बढ़ाने का भी प्रयास किया।

XI.52 संशोधित जोखिम रेटिंग और स्कोरिंग मॉडल पहले ही तैयार किया जा चुका है तथा एएमआरएमएस पैकेज में उपयुक्त परिवर्तन करने के बाद इसे जनवरी 2022 से लागू किया जाएगा। वर्ष 2021 की दूसरी छमाही के दौरान इस मॉडल का समानांतर रन मोड के तहत परीक्षण किया जाएगा।

वर्ष 2021-22 के लिए कार्ययोजना

XI.53 वर्ष के दौरान विभाग निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करेगा:

- परियोजना की लागत, समय और डिलिवरेबल्स के प्रभावी प्रबंधन का मूल्यांकन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि परियोजना का प्रबंधन प्रोजैक्ट उद्देश्यों के अनुरूप है, रिज़र्व बैंक के सभी पहचाने गए उच्च मूल्य आईटी और गैर-आईटी परियोजनाओं के लिए पूर्ण परियोजना लेखा परीक्षा को लागू करना (उत्कर्ष);
- आरबीआईए के तहत मूल्यांकन किए गए जोखिम-रेटिंग के साथ रैम-ओर के अनुसार जोखिम-रेटिंग के साथ पूर्ण अभिसरण प्राप्त करने का प्रयास करना (उत्कर्ष); तथा
- वर्ष 2021 की दूसरी छमाही के दौरान एएमआरएमएस पैकेज में उपयुक्त परिवर्तन करने और समानांतर रन मोड के तहत इसका परीक्षण करने के बाद जनवरी 2022 से रिज़र्व बैंक में संशोधित जोखिम रेटिंग और स्कोरिंग मॉडल को लागू करना।

6. कॉर्पोरेट कार्यनीति और बजट प्रबंधन

XI.54 कॉर्पोरेट कार्यनीति और बजट विभाग (सीएसबीडी) रिज़र्व बैंक की कार्यनीतियों का निर्माण और समन्वय करता है, वार्षिक बजट तैयार करता है और बजटीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए व्यय की निगरानी भी करता है। विभाग संकट समय के लिए सुदृढ़ कारोबार निरंतरता योजनाएं (बीसीपी) बनाता है और उसका कार्यान्वयन करता है तथा रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तपोषित बाह्य संस्थानों के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है।

XI.55 रिज़र्व बैंक के कारोबार निरंतरता प्रबंधन (बीसीएम) फ्रेमवर्क के लिए नोडल विभाग होने के नाते, सीएसबीडी ने,

कोविड-19 महामारी के दौरान अन्य आवश्यक गतिविधियों के साथ अपने समय संवेदनशील महत्वपूर्ण गतिविधियों के सुचारु संचालन को सुविधाजनक बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सभी क्षेत्रीय कार्यालयों/व्यावसायिक इकाइयों के लिए बीसीपी के देश व्यापी आह्वान को प्रौद्योगिकी के सहारे निपुणता से संभाला गया। रिज़र्व बैंक की सक्रिय आपदा प्रबंधन पहलों ने विशेष रूप से देश की भुगतान प्रणाली और सामान्य रूप से बैंकिंग प्रणाली के लिए निर्बाध 24x7 सेवाओं को सुनिश्चित करके पर्याप्त सुविधा प्रदान की है।

XI.56 सरकार के वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) के साथ रिज़र्व बैंक के लेखा वर्ष के एकत्रीकरण से संक्रांति वर्ष 2020-21 का बजट अनुमान नौ महीने (जुलाई 2020 से मार्च 2021) की अवधि के लिए तैयार किया गया। बजट अनुमान की तुलना में पूंजीगत व्यय के उपयोग में सुधार लाने के लिए केंद्रीय बोर्ड (सीसीबी) की समिति के अनुमोदन से पूंजीगत व्यय बफर का प्रावधान किया गया। रिज़र्व बैंक के व्यय फ्रेमवर्क के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को मजबूत करने के लिए व्यय नियमावली 2018 में संशोधन किया गया। वित्तीय अनुशासन को मजबूत करने और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) में सुधार के लिए ई-कुबेर के बिल भुगतान मॉड्यूल में भी व्यय नियमों को मैप किया गया है।

वर्ष 2020-21 के लिए कार्ययोजना- कार्यान्वयन की स्थिति

2020-21 के लिए निर्धारित लक्ष्य

XI.57 पिछले वर्ष विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- कार्यनीति लक्ष्यों/माइलस्टोन के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए प्रमुख कार्यनिष्पादन संकेतकों (केपीआई) पर आधारित फ्रेमवर्क लागू करने के लिए डैशबोर्ड प्रचालित करना (उत्कर्ष) [पैरा XI.58];
- बाह्य वित्तपोषित संस्थानों (ईएफआई) के आंतरिक गवर्नेंस को सुदृढ़ करना [पैरा XI.59]; और

- आईजीआईडीआर और कैफरल इन संस्थानों के साथ सहयोग को बढ़ाने के लक्ष्य से समझौता ज्ञापन (एमओयू) का नवीनीकरण करना [पैरा XI.60]; तथा

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

XI.58 केंद्रीय बोर्ड की कार्यनीति उप समिति के निर्देशों के अनुपालन में, 'उत्कर्ष 2022' के तहत विभिन्न माइलस्टोन और लक्ष्यों की पूर्ति का मूल्यांकन करने के लिए प्रमुख कार्यनिष्पादन संकेतक (केपीआई) फ्रेमवर्क लागू किया गया है (बॉक्स XI.2)। कार्यनीति लक्ष्यों/माइलस्टोन के कार्यान्वयन की केंद्रीकृत निगरानी के लिए डैशबोर्ड के विकास का कार्य शुरू कर दिया गया है। उक्त डैशबोर्ड विलंबित माइलस्टोन के लिए एक पूर्व चेतावनी प्रणाली का भी कार्य करेगा।

XI.59 वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों के अनुसरण में बाहरी वित्त पोषित संस्थानों के आंतरिक गवर्नेंस को सुदृढ़ करने के लिए निदेशकों की नियुक्ति और बोर्डों और उनकी उप-समितियों में उत्पन्न रिक्तियों को समय पर भरने जैसे कदम उठाए गए।

XI.60 रिज़र्व बैंक और आईजीआईडीआर के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) निष्पादित किया गया, जिसके अनुसार अंततः आईजीआईडीआर से वित्तीय आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने की अपेक्षा है।

वर्ष 2021-22 के लिए कार्ययोजना

XI.61 वर्ष के लिए विभाग की कार्ययोजना में निम्नलिखित शामिल हैं:

- कार्यनीति लक्ष्यों/माइलस्टोन प्राप्त न होने की संभावना के लिए एक इनबिल्ट पूर्व चेतावनी प्रणाली के साथ 'उत्कर्ष' डैशबोर्ड प्रचालित करना;
- कार्यनीति उप-समिति द्वारा कार्यनीति फ्रेमवर्क 'उत्कर्ष 2022' की मध्यावधि समीक्षा करना;

बॉक्स XI.2

रिज़र्व बैंक का कार्यनीति फ्रेमवर्क

रिज़र्व बैंक ने अप्रैल 2015 में एक औपचारिक कार्यनीति प्रबंधन फ्रेमवर्क तैयार किया और अपने मूल उद्देश्य, मूल्यों और विजन स्टेटमेंट की समकालीन संदर्भ में अपने कार्यनीतिगत उद्देश्यों को चित्रित करने तथा एक रूपरेखा और पृष्ठभूमि प्रदान करने की दृष्टि से फिर से पुष्टि की जिसके अनुसार इसकी नीतियां तैयार की जा सकती हैं। तदुपरांत, एक मध्यावधि गतिशील कार्यनीति फ्रेमवर्क की जरूरत महसूस की गई जो समय के साथ तेजी से उभरते गतिशील अर्थशास्त्र, सामाजिक और तकनीकी पारिस्थिति के तंत्र को पकड़ सके और उसका प्रतिसाद दे सके। इसके प्रतिसाद में जुलाई 2019 में रिज़र्व बैंक ने उत्कर्ष 2022 मध्यावधि कार्यनीति फ्रेमवर्क शुरू किया।

मध्यावधि कार्यनीति के रूप में उत्कर्ष 2022 के कार्यान्वयन का मार्गदर्शन और निगरानी रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की उच्चस्तरीय उप-समिति द्वारा की जा रही है जिसमें केंद्रीय बोर्ड के तीन निदेशक, कॉर्पोरेट कार्यनीति और बजट विभाग (सीएसबीडी) के उप गवर्नर तथा प्रभारी कार्यपालक निदेशक और प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक शामिल हैं। हालांकि अप्रत्याशित कोविड-19 महामारी के कारण निर्धारित माइलस्टोन प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा, फिर भी मार्च 2021 के अंत में 226 माइलस्टोन में से 169 माइलस्टोन का पूरी तरह कार्यान्वयन किया गया है, लक्ष्य के कार्यान्वयन के लिए अभी भी एक साल शेष है।

उत्कर्ष 2022 के तहत कार्यनीति माइलस्टोन की पूर्ति और उनके पालन की निगरानी प्रमुख निष्पादन संकेतक (केपीआई) फ्रेमवर्क के माध्यम से की जाती है। केपीआई फ्रेमवर्क माइलस्टोनों के लक्ष्यों को हासिल न करने की संभावना के पूर्व चेतावनी संकेतों को पकड़ने में उपयोगी है। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक की कार्यपद्धति और कार्य के सभी आयामों को पकड़ने के लिए माइलस्टोन को इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और आउटकम माइलस्टोन के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी का अचानक और तेजी से प्रसार, और परिणामी देशव्यापी लॉकडाउन ने उत्कर्ष 2022 की आघात सहनीयता का परीक्षण किया। रिज़र्व बैंक के अधिकांश कार्यों के संचालन के तरीकों में लॉकडाउन द्वारा उत्पन्न परिवर्तनों ने, बैंकिंग प्रणाली के साथ-साथ, बैंकिंग की

रूपरेखा को भी कई प्रकार से बदल दिया। जबकि कुछ परिवर्तन अल्पकालिक होंगे, कई ऐसे होंगे जो बैंकिंग सेवाओं के वितरण और उपयोग के तरीके को स्थायी रूप से बदल देंगे। कार्य के डिजिटल तरीके में बदलाव और फिनटेक कंपनियों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा बैंकिंग प्रणाली के लिए नई चुनौतियां और अवसर लेकर आई है।

कार्यनीति उप-समिति के मार्गदर्शन में, सभी विभागों ने कोविड-19 महामारी के आलोक में अपनी कार्यनीतियों की समीक्षा की है। विभागों ने बैंकिंग सेवाओं पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव की सक्रिय रूप से निगरानी की है और व्यवधानों का मुकाबला करने और करोबार निरंतरता, साइबर सुरक्षा और भुगतान प्रणाली के निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करने के उपाय किए हैं। बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा कोविड-19 से उत्पन्न चुनौतियों का भी प्रभावी ढंग से सामना किया गया है।

संगठन के भविष्य को आकार देने में कार्यनीति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, साथ ही इसके मूल मिशन और विजन को पूरा करने में भी मदद करती है। यहां तक कि जब हम कोविड-19 के अंधकार से उभरने लगे हैं, रिज़र्व बैंक का कार्यनीति फ्रेमवर्क यह मानता है कि नए खतरे और अवसर अचानक सामने आ सकते हैं। इसलिए रिज़र्व बैंक का कार्यनीति फ्रेमवर्क उभरते खतरों और अवसरों के प्रति गतिशील, उद्विक्तासी और प्रतिक्रियाशील होने का प्रयास करता है।

जुलाई 2019 में इसकी शुरुआत के बाद से, उत्कर्ष 2022 ने मार्च 2021 तक अपना आधा मार्ग तय कर लिया है। देश भर में बैंकिंग और भुगतान सेवाओं के वितरण में थोड़ी सी भी रुकावट के बिना वैश्विक महामारी से बचे रहना कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। परंतु इस तरह के कठिन दौर में किसी भी प्रकार की शिथिलता के लिए कोई गुंजाइश नहीं हो सकती। इसलिए, कार्यनीति उप-समिति, 2021 में उत्कर्ष 2022 की मध्यावधि समीक्षा करने के लिए तैयार है। इस अभ्यास से यह पता चलेगा कि क्या कारगर रहा और क्या नहीं, और भविष्य के लिए कार्यनीति बनाते समय रडार को कहां रखना है, इस पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा।

स्रोत: आरबीआई

- महामारी के लिए एक बीसीएम फ्रेमवर्क तैयार करना; तथा
- अतिरिक्त बजट स्वीकृति को तर्कसंगत बनाना और प्रक्रिया को स्वचालित करना;

7. राजभाषा

XI.62 भारत सरकार की राजभाषा नीति के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रति स्टाफ सदस्यों को संवेदनशील बनाने की जिम्मेदारी राजभाषा विभाग को सौंपी गई है। तदनुसार, विभाग ने द्विभाषणीकरण की अपेक्षाओं का अनुपालन करना; पत्राचार और आंतरिक कार्य में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए स्टाफ सदस्यों को हिंदी भाषा का प्रशिक्षण देना; और विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से अपने कार्य को हिंदी में करने के लिए स्टाफ सदस्यों को प्रोत्साहित और प्रेरित करना; सुनिश्चित किया है। विभाग ने राजभाषा नीति के अनुपालन की प्रगति की समीक्षा के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निगरानी की। विभाग राजभाषा पर भारत के राष्ट्रपति के आदेशों, वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यों के साथ-साथ संसदीय राजभाषा समिति को उनके दौरों के दौरान दिए गए आश्वासन तथा भारत सरकार से समय-समय पर प्राप्त निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित करता है।

वर्ष 2020-21 के लिए कार्ययोजना – कार्यान्वयन स्थिति

2020-21 के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य

XI.63 पिछले वर्ष, विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- बैंकिंग शब्दावली को अद्यतन करना (पैरा XI.64);
- हिन्दी के प्रयोग के संबंध में वार्षिक कार्यक्रम और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य दिशा-निर्देशों का कार्यान्वयन करना (पैरा XI.65);
- हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए विभाग संबंधी विशेष शब्दावलियां तैयार करना (पैरा XI.66);
- कर्मचारियों में हिंदी संबंधी सृजनात्मकता को बढ़ाने के प्रयोजन से क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए हिंदी पत्रिकाओं की प्रतियोगिता प्रारंभ करना (पैरा XI.67);

- हिंदी के प्रयोग संबंधी अद्यतन अनुदेशों/दिशा-निर्देशों के संबंध में जानकारी देने के लिए केंद्रीय कार्यालय विभागों/क्षेत्रीय कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए हिंदी कार्यशाला आयोजित करना (पैरा XI.68); और
- बैंकिंग विषयों पर हिंदी व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन करना (पैरा XI.68)।

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

XI.64 वर्तमान में, बैंकिंग शब्दावली को अद्यतन किया जा रहा है। राजभाषा विभाग ने बैंकिंग शब्दावली को अद्यतन करने के लिए बैंकों और प्रख्यात विद्वानों को शामिल करते हुए एक अंतर-संस्था समिति का गठन किया है। समिति की पहली बैठक 2 मार्च 2021 को हुई। अद्यतनीकरण का कार्य अगले दो साल में (दिसंबर 2022 तक) पूरा होने की उम्मीद है।

XI.65 हिंदी के प्रयोग के संबंध में गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम सभी क्षेत्रीय कार्यालयों (क्षेका) और केंद्रीय कार्यालय विभागों (केंकावि) को कार्यान्वयन के लिए परिचालित किया गया था। केंद्रीय कार्यालय विभागों और क्षेत्रीय कार्यालयों ने सरकार द्वारा निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त किया है।

XI.66 हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए, विनियमन, विदेशी मुद्रा, आर्थिक अनुसंधान और नीति, परिसर, विधि, मुद्रा प्रबंधन और शिष्टाचार और सुरक्षा सहित कुछ विभागों के लिए विभाग-विशिष्ट शब्दावली तैयार करने का काम पूरा किया गया है।

XI.67 स्टाफ सदस्यों के बीच हिंदी में रचनात्मकता को बढ़ाने के उद्देश्य से, वर्ष 2020-21 से क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए हिंदी पत्रिका प्रतियोगिता शुरू की गई है। तदनुसार, वर्ष 2020-21 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रकाशित पत्रिका का मूल्यांकन 2021-22 के दौरान किया जाएगा।

XI.68 विभिन्न क्षेका/केंका के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए जुलाई 2020-मार्च 2021 के दौरान कुल 12 हिंदी कार्यशालाएं

आयोजित की गई थी। इसके अलावा, राजभाषा अधिकारियों के लिए “व्याख्यान मंच” के तहत “भुगतान और निपटान प्रणाली”, ‘आरबीआई वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 के महत्वपूर्ण पहलू’, ‘एनबीएफसी के विनियमन का अवलोकन’ और ‘वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट - जनवरी 2021’ जैसे चार व्याख्यान हिंदी में आयोजित किए गए थे।

प्रमुख गतिविधियां

XI.69 जुलाई 2020-मार्च 2021 के दौरान 118 स्टाफ सदस्यों ने प्राज्ञ² की परीक्षा उत्तीर्ण की और 159 ने पारंगत³ परीक्षा उत्तीर्ण की। केंका और क्षेका के स्टाफ सदस्यों को कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करने का प्रशिक्षण दिया गया। केंका और क्षेका ने हिंदी समारोह और विविध बैंकिंग विषयों पर सेमिनार आयोजित करके हिंदी दिवस मनाया और हिंदी के प्रयोग के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं और कार्यक्रम आयोजित किए।

प्रशिक्षण

XI.70 रिजर्व बैंक के विजन वक्तव्य ‘उत्कर्ष 2022’ जो वर्तमान और भावी चुनौतियों के लिए मानव संसाधन के कौशल उन्नयन के बारे में बताता है, के अनुसरण में राजभाषा अधिकारियों के एक बैच को आंचलिक प्रशिक्षण केंद्र कोलकाता द्वारा सामान्य बैंकिंग पर प्रशिक्षण दिया गया। राजभाषा निरीक्षणों की प्रभावकारिता बढ़ाने के उद्देश्य से राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा अधिकारियों के एक बैच को राजभाषा निरीक्षण के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके अलावा, आरबीएससी, चेन्ने द्वारा ‘अनुवाद में उपयोगी नवीनतम बैंकिंग अवधारणाओं’ पर राजभाषा अधिकारियों के लिए एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

प्रकाशन

XI.71 रिजर्व बैंक के सांविधिक प्रकाशनों अर्थात् वार्षिक रिपोर्ट, भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, मौद्रिक नीति रिपोर्ट और अन्य प्रकाशनों जैसे कि वित्तीय स्थिरता

रिपोर्ट, साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक और भारतीय रिजर्व बैंक के मासिक बुलेटिनों को द्विभाषिक रूप में प्रकाशित किया गया और ये रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। विभाग द्वारा रिजर्व बैंक में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को प्रस्तुत करने वाले राजभाषा समाचार के अलावा हिंदी पत्रिका बैंकिंग चिंतन अनुचिंतन का भी प्रकाशन किया गया।

संसदीय राजभाषा समिति को दिए गए आश्वासनों का अनुपालन

XI.72 संसदीय राजभाषा समिति हिंदी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा के लिए नियमित रूप से रिजर्व बैंक के केंद्रीय कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों का दौरा करती है। रिजर्व बैंक की केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति इस समिति को दिए गए आश्वासनों के अनुपालन की निगरानी करती है। वर्ष के दौरान, हिंदी विज्ञापनों पर व्यय की निगरानी, अधिक से अधिक स्टाफ-सदस्यों को पारंगत का प्रशिक्षण देने, हिंदी संवर्ग के खाली पदों को भरने, क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी अधिकारियों द्वारा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों (नराकास) में भाग लेने के लिए ठोस कदम उठाए गए।

XI.73 राजभाषा पर संसदीय समिति की प्रारूप और साक्ष्य उप-समिति ने नराकास, दिल्ली के तत्वावधान में 17 नवंबर 2020 को दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय में हिंदी के प्रयोग की समीक्षा की और कार्यालय की प्रगति संतोषजनक पाई गई।

एकीकृत राजभाषा रिपोर्टिंग प्रणाली

XI.74 रिजर्व बैंक में हिंदी के प्रयोग से संबंधित आंकड़ों के संग्रहण, प्रसंस्करण, रिपोर्टिंग और संग्रह के लिए सितंबर 2020 में एकीकृत राजभाषा रिपोर्टिंग प्रणाली (आईआरआरएस) पैकेज का उद्घाटन किया गया और इसे लाइव बनाया गया। इस पैकेज के माध्यम से तिमाही प्रगति रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट, हिंदी सलाहकार समिति की रिपोर्ट, वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट, नराकास की रिपोर्ट और हिंदी ज्ञान का रोस्टर जैसी विभिन्न रिपोर्टें तैयार की जा रही हैं। आईआरआरएस पैकेज ने ‘कम पेपर’ और स्वचालित कार्य के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाया है।

² यह परीक्षा उन के लिए आयोजित की जाती है जिनको हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं है।

³ हिंदी में प्रवीणता प्राप्त करने के लिए उच्चतर परीक्षा।

वर्ष 2021-22 के लिए कार्ययोजना

XI.75 वर्ष के दौरान निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करने की विभाग की योजना है:

- 'राजभाषा नीति: एक परिचय' पर एक पुस्तिका प्रकाशित करने और स्टाफ सदस्यों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए इसका प्रसार करना;
- भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम और अन्य निर्देशों के अनुसार राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए वार्षिक कार्य योजना तैयार करना और इसे सभी क्षेत्रों/केंद्रों को एक तैयार रेकनर के रूप में परिचालित करना;
- रिजर्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए राजभाषा नीति पर कार्यक्रम आयोजित करना;
- राजभाषा निरीक्षण की प्रभावकारिता बढ़ाने के लिए राजभाषा अधिकारियों को राजभाषा निरीक्षण पर प्रशिक्षण देना;
- हिंदी के प्रयोग के संबंध में निगरानी प्रणाली को मजबूत करने के लिए क्षेत्रों/केंद्रों में तैनात राजभाषा अधिकारियों के साथ तीनों क्षेत्रों (यानी क, ख और ग) के लिए क्षेत्रवार समीक्षा बैठक आयोजित करना;
- द्विभाषीकरण सुनिश्चित करने के लिए रिजर्व बैंक की वेबसाइट/ईकेपी पर अपलोड किए गए एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर और सामग्रियों की निगरानी करना; और
- अनुवाद प्रणाली को मजबूत करने के लिए राजभाषा अधिकारियों के लिए अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना; और नियमित अंतराल पर अनुवाद समीक्षा समिति की बैठकों का आयोजन भी करना।

8. परिसर विभाग

XI.76 परिसर विभाग का विजन रिजर्व बैंक के परिसरों में वास्तुशिल्पीय उत्कृष्टता और सौंदर्यात्मक आकर्षण के समेकन के साथ ग्रीन रेटिंग से 'अपनी श्रेणी में सर्वोत्तम' और पर्यावरण अनुकूल भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के साथ ही उच्चतम स्तर की सफाई सुनिश्चित करना है।

वर्ष 2020-21 के लिए कार्ययोजना : कार्यान्वयन की स्थिति

2020-21 के लिए निर्धारित लक्ष्य

XI.77 पिछले वर्ष, विभाग द्वारा निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए थे:

- सभी नई भवन परियोजनाओं के अतिरिक्त कम से कम एक कार्यालय और पांच मौजूदा आवासीय इमारतों के लिए जीआरआईएचए/आईजीबीसी⁴ से ग्रीन रेटिंग प्रमाणन प्राप्त करना (उत्कर्ष) [पैरा XI.78];
- नवीकरणीय स्रोतों से 3.0 प्रतिशत ऊर्जा खपत प्राप्त करना (उत्कर्ष) [पैरा XI.78];
- 2.5 प्रतिशत ऊर्जा बचत करना (उत्कर्ष) [पैरा XI.78];
- 5.0 प्रतिशत जल संरक्षण/बचत प्राप्त करना (उत्कर्ष) [पैरा XI.78];
- माल सूची और आस्टि ट्रैकिंग को आरईबीआईटी के सहयोग से डिजिटल बनाना (उत्कर्ष) [पैरा XI.78];
- चेन्नै, मुंबई और दिल्ली की आवासीय परियोजनाओं को पूरा करना और अगरतला, इंफाल और रांची में बाउंड्री दीवार का निर्माण करना (पैरा XI.79);
- नया रायपुर में कार्यालय परिसर और देहरादून, खारघर, नवी मुंबई और जम्मू में आवासीय परियोजनाओं का निर्माण कार्य प्रारंभ करना (पैरा XI.79); और

⁴ इंटीग्रेटेड हैबिटेट एसेसमेंट (जीआरआईएचए)/इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (आईजीबीसी) के लिए ग्रीन रेटिंग।

- संविदा आर्किटेक्चर⁵ की समीक्षा और संशोधन करना और परियोजनाओं की निगरानी के लिए परियोजना प्रबंधन टूल्स⁶ का कार्यान्वयन(पैरा XI.80)।

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

XI.78 वर्ष 2020-21 में, विकास विजन से प्रेरित था, क्योंकि विभाग ने इन क्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास किया। उत्कर्ष के तहत निर्धारित कई लक्ष्यों को विभाग ने पार कर लिया है। गृह/आईजीबीसी से कम से कम एक मौजूदा कार्यालय भवन और पांच मौजूदा आवासीय इमारतों के लिए, संबंधित ग्रीन रेटिंग प्राप्त करने के लक्ष्य की तुलना में जनवरी 2020-जनवरी 2021 के दौरान कुल तीन कार्यालय भवनों और दस आवासीय इमारतों के लिए आईजीबीसी से ग्रीन रेटिंग प्राप्त की है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान कोई नयी इमारत नहीं बनी है। सभी रिज़र्व बैंक के परिसरों में नवीकरणीय स्रोतों से आधार वर्ष (जून 2018 को समाप्त वर्ष) के 3.0 प्रतिशत बिजली की खपत प्राप्त करने के लक्ष्य के मुकाबले, जनवरी 2021 में नवीकरणीय स्रोतों से समग्र ऊर्जा उत्पादन 4.2 प्रतिशत था। रिज़र्व बैंक ने जून 2018 को समाप्त आधार वर्ष में वार्षिक खपत की तुलना में जनवरी 2021 तक 2.5 प्रतिशत के लक्ष्य के मुकाबले 30.1 प्रतिशत की ऊर्जा बचत की है। जून 2018 को समाप्त आधार वर्ष में वार्षिक खपत की तुलना में जनवरी 2021 (वर्ष-दर-वर्ष) में जल संरक्षण/बचत 5.0 प्रतिशत के लक्ष्य के मुकाबले 21.5 प्रतिशत अधिक थी। ऊर्जा लेखा परीक्षा की सिफारिशों को लागू करने से केंद्रीय एयर कंडीशनिंग संचालन और अन्य विद्युत उपकरणों के प्रदर्शन में सुधार, चरणबद्ध तरीके से पारंपरिक लाइट के स्थान पर एलईडी लाइटों का प्रतिस्थापन, पुराने उपकरणों के स्थान पर उर्जा कुशल तथा उर्जा दक्षता

ब्यूरो (बीईई) द्वारा स्टार रेटेड उपकरणों की प्रतिस्थापना और पारंपरिक नल के स्थान पर सेंसर-आधारित नल की प्रतिस्थापन से लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक अहम भूमिका निभाई, ऊर्जा बचत और पानी के संरक्षण में भारी वृद्धि मुख्य रूप से अप्रैल से दिसंबर 2020 के दौरान कोविड-19 प्रेरित लॉकडाउन/प्रतिबंधों से कार्यालय के सीमित कार्य के घंटों के कारण हुई। रेबिट के सहयोग से इन्वेंट्री और फिक्स्ड एसेट ट्रैकिंग को डिजिटाइज़ करने की प्रक्रिया और इस तरह फिक्स्ड एसेट मैनेजमेंट सिस्टम का कार्यान्वयन मार्च 2021 के अंत तक 72 प्रतिशत क्षेका में पूरा हो गया था। जहां कोविड से संबंधित लॉकडाउन के कारण कुछ क्षेका में काम की गति बाधित हुई, वहीं विक्रेताओं की सीमित उपलब्धता ने भी इस काम को पूरा न करने में अपनी भूमिका निभाई।

XI.79 चेन्नै (अन्ना नगर), मुंबई (चेंबूर) और दिल्ली (हौज खास) में आवासीय परियोजनाओं का निर्माण कोविड से संबंधित लॉकडाउन से प्रभावित हुआ। हालांकि, चेन्नै और दिल्ली परियोजनाएं पूरी होने के अंतिम चरण में हैं। इंफाल और अगरतला में रिज़र्व बैंक के कार्यालय भूखंडों के लिए बाउंड्री दीवार का निर्माण लक्ष्य के अनुसार पूरा कर लिया गया है। रांची कार्यालय के भूखंड पर बाउंड्री दीवार निर्माण के लिए व्यय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और 2021-22 में कार्य का निष्पादन निर्धारित किया गया है। देहरादून आवासीय परियोजना अनुमोदन के अंतिम चरण में है, जबकि जम्मू आवासीय परियोजना के लिए निविदा दस्तावेजों की जांच की जा रही है। यह सभी परियोजनाएं 2021-22 में शुरू होने की संभावना है।

XI.80 'डिपाज़िट' कार्य आधार पर परियोजनाओं के लिए कॉन्ट्रैक्ट आर्किटेक्चर की समीक्षा और संशोधन पूरा कर लिया गया है और परियोजना प्रबंधन सॉफ्टवेयर का कार्यान्वयन के

⁵ निर्माण परियोजनाओं की योजना बनाने से लेकर समाप्ति तक को कवर करने वाले फ्रेमवर्क को संदर्भित करता है।

⁶ ये सॉफ्टवेयर समाधान हैं जो परियोजनाओं की निगरानी और प्रभावी प्रबंधन में सहायता प्रदान करते हैं।

लिए वर्तमान में उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण चल रहा है और 2021-22 में लाइव होने की उम्मीद है।

प्रमुख गतिविधियां

निर्माण गतिविधियां

XI.81 मुंबई में सेंटर फॉर एडवांस्ड फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग (सीएएफआरएल) संस्था की इमारत की संरचना पूरी हो चुकी है। शेष संरचना कार्य और फिनिशिंग कार्य प्रगति पर है। देहरादून में कार्यालय भवन का निर्माण शुरू हो गया है।

कोविड-19 के खिलाफ निवारक उपाय

XI.82 विभाग ने कोविड-प्रेरित लॉकडाउन के दौरान कार्यालय में उपस्थित होने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सभी एयर हैंडलिंग यूनिट्स (एएचयू) में मिनिमम एफिशिएंसी रिपोर्टिंग वैल्यू-13 (एमईआरवी-13) फिल्टर्स और अल्ट्रा वायलेट जर्मिसिडल इराडिएशन (यूवीजीआई) असेंबलिंग के प्रावधान सहित केंद्रीय कार्यालय भवन में कई उपाय किए।

हरित पहल (उत्कर्ष के तहत लक्षित से इतर)

XI.83 रिजर्व बैंक ने विभिन्न कार्यालयों और आवासीय कालोनियों में स्थापित सौर ऊर्जा जनरेशन संयंत्रों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा जनरेट की। जुलाई 2020-मार्च 2021 के दौरान 18 आवासीय कॉलोनियों में सोलर पावर प्लांट लगाए गए हैं। नतीजतन, मार्च 2021 के अंत तक 26 कार्यालय परिसरों और 44 आवासीय परिसरों में ऐसे सौर ऊर्जा संयंत्र थे, जिसमें सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता 2,034 किलोवाट केडब्ल्यूपी (किलोवाट पीक) [जून 2020] से बढ़कर 2,504 किलोवाट हो गई (मार्च 2021)। जल संसाधनों के संरक्षण और कुशल प्रबंधन के लिए 17 कार्यालय और 40 आवासीय परिसरों में जल उपचार संयंत्र तथा 3 कार्यालय और 11 आवासीय इमारतों में सीवेज उपचार संयंत्र लगाए गए। 11 कार्यालयों तथा 43 आवासीय परिसरों में ऑर्गनिक अवशिष्ट कनवर्टर भी स्थापित किए गए हैं।

अन्य नवोन्मेषी कार्य

XI.84 अहमदाबाद और रांची कार्यालयों के लिए अतिरिक्त कार्यालय परिसर पट्टे पर लिया गया और पणजी, गोवा में कार्यालय परिसर के निर्माण के लिए तथा आइजोल, मिजोरम में कार्यालय और आवासीय परिसर के लिए संबंधित राज्य सरकारों से भूमि अधिग्रहण किया गया।

XI.85 विभाग के पास विभिन्न कार्यालयों की योजनाओं के लगभग 23,000 चित्र और ट्रेसिंग हैं। सभी चित्रों और ट्रेसिंग को उन तक आसान पहुंच और कुशल रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए डिजिटलाइज्ड और ई-इंडेक्स किया गया है।

XI.86 उत्कर्ष डेटा के समेकन और विश्लेषण और अन्य हरित पहलों और क्षेका से प्राप्त ऊर्जा/जल लेखा परीक्षा के बारे में जानकारी के लिए ग्रीन (जनरेशन ऑफ रेनोवेबल एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन एण्ड नीर कंजर्वेशन) नाम का एक वेब-आधारित मंच ऊर्जा दक्षता/संरक्षण में सुधार लाने के उद्देश्य से रेबिट के परामर्श से विकसित किया गया है। मंच का उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण (यूएटी) चल रहा है।

XI.87 वर्तमान में ₹5 लाख रुपये से अधिक की सभी निविदाएं ई-निविदा के माध्यम से एमएसटीसी पोर्टल का उपयोग करके आमंत्रित की जा रही हैं। वर्ष के दौरान केंका, क्षेका और प्रसं द्वारा 770 ई-टेंडर निकाले गए। इसके अलावा सामग्री (स्क्रेप और अप्रचलित सामग्री) की बिक्री में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए एमएसटीसी लिमिटेड के साथ एक समझौता किया गया था और एमएसटीसी पोर्टल पर ई-नीलामी द्वारा एक ही लेन-देन में ₹5 लाख रुपये और उससे अधिक माल/स्क्रेप की बिक्री करने के लिए सभी क्षेका/प्रसं को दिशा-निर्देश जारी किए गए थे।

वर्ष 2021-22 के लिए कार्ययोजना

XI.88 वर्ष 2021-22 के लिए, विभाग द्वारा निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं:

- जनवरी 2022 के लिए उत्कर्ष के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना और सुधार करना;

- चेन्नै (अन्ना नगर) और दिल्ली (हौज खास) में आवासीय परियोजनाएं जो पूरा होने के करीब हैं; का अधिग्रहण;
- नया रायपुर में कार्यालय परिसर का निर्माण, देहरादून और जम्मू में आवासीय परियोजनाएं और मुंबई (खारघर) में आवासीय के साथ-साथ जेडटीसी परियोजना का निर्माण शुरू करना;
- शिलांग और रांची में बाउंड्री दीवार का निर्माण करना;
- प्रमुख परियोजनाओं की निगरानी के लिए एंटरप्राइज परियोजना प्रबंधन सॉफ्टवेयर के कार्यान्वयन के लिए यूएटी से उत्पादन में शिफ्ट होना;
- ऑनलाइन समेकन और उत्कर्ष डेटा के विश्लेषण तथा अन्य हरित पहलों और शेका से प्राप्त ऊर्जा/जल लेखा परीक्षा के बारे में जानकारी के लिए ग्रीन डेटा प्लेटफॉर्म को लागू करना; और
- हरित पहल जारी रखना।

9. निष्कर्ष

XI.89 संक्षेप में, यह अध्याय रिजर्व बैंक में गवर्नेस तथा मानव संसाधन के क्षेत्रों से संबंधित गतिविधियों और जोखिम निगरानी और आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए किए गए उपायों का स्नेपशॉट देता है। एचआरएमडी ने वर्ष के दौरान क्लाउड-आधारित वीडियो अनुप्रयोगों का उपयोग करके वर्चुअल मोड में कर्मचारियों के लिए विभिन्न कौशल बढ़ाने वाले कार्यक्रम आयोजित किए। राजभाषा विभाग द्वारा भारत सरकार के राजभाषा अधिनियम के सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया गया, वहीं परिसर विभाग ने पर्यावरण अनुकूल भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के अपने प्रयास जारी रखे। विभागों ने वर्ष के लिए निर्धारित अपने लक्ष्यों का मूल्यांकन किया तथा वर्ष 2021-22 के लिए अपनी कार्ययोजना निर्धारित की है। कोविड-19 के प्रकोप के साथ, अपने मानव संसाधनों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करते हुए, रिजर्व बैंक ने अपनी समय संवेदनशील महत्वपूर्ण गतिविधियों की कारोबार निरंतरता और सुचारू कामकाज सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कारोबारी प्रक्रियाओं को सुरक्षित किया।

सारणी XI.1 : 1 जुलाई 2020 - 31 मार्च 2021 के दौरान केंद्रीय निदेशक बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति

सदस्य का नाम	आरबीआई अधिनियम, 1934 के अंतर्गत नियुक्त/नामित	आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया
1	2	3	4
शक्तिकान्त दास	8(1)(ए)	5	5
बी. पी. कानूनगो [^]	8(1)(ए)	5	5
महेश कुमार जैन	8(1)(ए)	5	5
माइकल देबब्रत पात्र	8(1)(ए)	5	5
एम.राजेश्वर राव*	8(1)(ए)	4	4
प्रसन्न कुमार मोहंती @	8(1)(बी)	3	3
दिलीप एस. शंघवी#	8(1)(बी)	4	4
रेवती अय्यर	8(1)(बी)	5	5
सचिन चतुर्वेदी	8(1)(बी)	5	4
नटराजन चंद्रसेकरन	8(1)(सी)	5	5
अशोक गुलाटी@	8(1)(सी)	3	3
मनीष सभरवाल@	8(1)(सी)	3	3
सतीश काशीनाथ मराठे	8(1)(सी)	5	5
स्वामीनाथन गुरुमूर्ति	8(1)(सी)	5	5
देबाशीष पंडा	8(1)(डी)	5	5
तरुण बजाज	8(1)(डी)	5	5

[^] 2 अप्रैल 2021 तक उपगवर्नर

* 9 अक्टूबर 2020 से उपगवर्नर

@ 8 फरवरी 2021 तक निदेशक

10 मार्च 2021 तक निदेशक

सारणी XI.2 : 1 जुलाई 2020 - 31 मार्च 2021 के दौरान केंद्रीय बोर्ड की समितियों की बैठकों में उपस्थिति

सदस्य का नाम	आरबीआई अधिनियम, 1934 के अंतर्गत नियुक्त/नामित	आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया
1	2	3	4
केंद्रीय बोर्ड समिति (सीसीबी)			
शक्तिकान्त दास	8(1)(ए)	35	33
बी. पी. कानूनगो [^]	8(1)(ए)	35	33
महेश कुमार जैन	8(1)(ए)	35	33
माइकल देबब्रत पात्र	8(1)(ए)	35	35
एम.राजेश्वर राव*	8(1)(ए)	21	21
प्रसन्न कुमार मोहंती @	8(1)(बी)	11	11
दिलीप एस. शंघवी#	8(1)(बी)	13	13
रेवती अय्यर	8(1)(बी)	12	11
सचिन चतुर्वेदी	8(1)(बी)	12	12
नटराजन चंद्रसेकरन	8(1)(सी)	12	6
अशोक गुलाटी@	8(1)(सी)	11	7
मनीष सभरवाल@	8(1)(सी)	10	9
सतीश काशीनाथ मराठे	8(1)(सी)	12	10
स्वामीनाथन गुरुमूर्ति	8(1)(सी)	11	1
तरुण बजाज	8(1)(डी)	26	26

[^] 2 अप्रैल 2021 तक उपगवर्नर

* 9 अक्टूबर 2020 से उपगवर्नर

@ 8 फरवरी 2021 तक निदेशक

10 मार्च 2021 तक निदेशक

II. वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस)

शक्तिकान्त दास	अध्यक्ष	9	9
महेश कुमार जैन	उपाध्यक्ष	9	9
बी पी कानूनगो [^]	सदस्य	9	9
माइकल देबब्रत पात्र	सदस्य	9	6
एम.राजेश्वर राव*	सदस्य	6	6
अशोक गुलाटी#	सदस्य	7	6
सतीश काशीनाथ मराठे	सदस्य	9	9
सचिन चतुर्वेदी	सदस्य	9	9

[^] 2 अप्रैल 2021 तक उपगवर्नर

* 9 अक्टूबर 2020 से उपगवर्नर

8 फरवरी 2021 तक सदस्य

III. भुगतान एवं निपटान प्रणाली विनियमन एवं पर्यवेक्षण बोर्ड (बीपीएसएस)

शक्तिकान्त दास	अध्यक्ष	2	2
बी. पी. कानूनगो@	उपाध्यक्ष	2	2
महेश कुमार जैन	सदस्य	2	2
माइकल देबब्रत पात्र	सदस्य	2	2
एम.राजेश्वर राव*	सदस्य	1	1
नटराजन चंद्रसेकरन	सदस्य	2	1
मनीष सभरवाल [^]	सदस्य	1	1

[^] 2 अप्रैल 2021 तक उपगवर्नर

* 9 अक्टूबर 2020 से उपगवर्नर

#8 फरवरी 2021 तक सदस्य

सारणी XI.3 : 1 जुलाई 2020 - 31 मार्च 2021 के दौरान बोर्ड की उप समितियों की बैठक में उपस्थिति

सदस्य का नाम	आरबीआई अधिनियम, 1934 के अंतर्गत नियुक्त/ नामित	आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया
1	2	3	4

I. लेखापरीक्षा एवं जोखिम प्रबंधन उप समिति (एआरएमएस)

रेवती अय्यर	अध्यक्ष	6	6
अशोक गुलाटी [^]	सदस्य	4	3
एम.राजेश्वर राव* सदस्य	सदस्य	3	3
बी पी कानूनगो@	आमंत्रित	6	6
महेश कुमार जैन	आमंत्रित	6	6
माइकल देब्रत पात्र	आमंत्रित	6	6

[^]: 8 फरवरी 2021 तक सदस्य   * : 9 अक्टूबर 2020 से सदस्य   @: 2 अप्रैल 2021 तक आमंत्रित

II. भवन उप समिति (बीएससी)

दिलीप एस. शंघवी*	अध्यक्ष	2	2
प्रसन्न कुमार मोहंती [^]	सदस्य	1	1
महेश कुमार जैन	सदस्य	2	2

[^]: 10 मार्च 2021 तक अध्यक्ष   * : 8 फरवरी 2021 तक सदस्य

III. मानव संसाधन प्रबंध उप समिति (एचआरएम-एससी)

मनीष सभरवाल*	अध्यक्ष	2	2
दिलीप शंघवी#	सदस्य	2	2
महेश कुमार जैन	सदस्य	2	2

* : 8 फरवरी 2021 तक अध्यक्ष   # : 10 मार्च 2021 तक सदस्य

IV. सूचना प्रौद्योगिकी उप समिति (आईटी-एससी)

मनीष सभरवाल [^]	अध्यक्ष	4	4
सचिन चतुर्वेदी	सदस्य	4	3
बी.पी. कानूनगो@	सदस्य	4	3

[^]; 8 फरवरी 2021 तक अध्यक्ष   @: 2 अप्रैल 2021 तक सदस्य

V. कार्यनीति उप-समिति

प्रसन्न कुमार मोहंती [^]	अध्यक्ष	2	2
मनीष सभरवाल#	सदस्य	2	2
रेवती अय्यर	सदस्य	2	2
बी. पी. कानूनगो@	सदस्य	2	2
महेश कुमार जैन	सदस्य	2	2
माइकल देब्रत पात्र	सदस्य	2	2
एम.राजेश्वर राव*	सदस्य	1	1

[^]: 8 फरवरी 2021 तक अध्यक्ष   # : 8 फरवरी 2021 तक सदस्य

@: 2 अप्रैल 2021 तक सदस्य   * : 9 अक्टूबर 2020 से सदस्य

सारणी XI.4 : 1 जुलाई 2020 - 31 मार्च 2021 के दौरान स्थानीय बोर्डों की बैठकों में उपस्थिति

सदस्य का नाम	आरबीआई अधिनियम, 1934 के अंतर्गत नियुक्त/नामित	आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया
1	2	3	4
सचिन चतुर्वेदी, ईएएलबी	धारा 9(1)	2	2
सुनील मित्रा*, ईएएलबी	धारा 9(1)	2	2
दिलीप एस. शंघवी#, डब्ल्यूएएलबी	धारा 9(1)	2	2
वी. आर. भानुशाली, डब्ल्यूएएलबी	धारा 9(1)	2	2
रेवती अय्यर, एनएएलबी	धारा 9(1)	3	3
आर.एन.दुबे, एनएएलबी	धारा 9(1)	3	3
प्रसन्न कुमार मोहंती, एसएएलबी^	धारा 9(1)	0	0

ईएएलबी: पूर्वी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड
एनएएलबी: उत्तरी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड

डब्ल्यूएएलबी: पश्चिमी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड
एसएएलबी: दक्षिणी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड

^: आवश्यक कोरम में कमी के कारण एसएएलबी कार्य नहीं कर सका।

#: 10 मार्च 2021 तक निदेशक

*: 8 फरवरी 2021 तक सदस्य

सारणी XI.5: 1 जुलाई 2020 - 31 मार्च 2021 के दौरान स्थानीय बोर्ड/बोर्डों के स्थान पर केंद्रीय निदेशक बोर्ड की स्थायी समिति की बैठक में उपस्थिति

सदस्य का नाम	आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया
1	2	3
प्रसन्न कुमार मोहंती@, अध्यक्ष	2	2
सतीश काशीनाथ मराठे, सदस्य	2	2

@: 8 फरवरी 2021 तक अध्यक्ष

टिप्पणी: दक्षिणी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड के स्थान पर आयोजित बैठकें।